

भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- †5117
उत्तर देने की तारीख- 04/04/2022
प्रधानमंत्री वन धन योजना

†5117. श्री कुनार हेम्ब्रम:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार झारग्राम जिले सहित पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री वन धन योजना कार्यान्वित कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल के दूरस्थ जनजातीय गांवों में बने उत्पादों के विपणन के लिए कोई पहल की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ लिमिटेड (ट्राइफेड) को दिए गए सहायता अनुदान का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(श्रीमती रेणुका सिंह सरुता)

(क): जनजातीय कार्य मंत्रालय प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन अन्य बातों के साथ-साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वनोपज (एमएफपी) के विपणन के लिए तंत्र और एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला के विकास घटक के साथ प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन को कार्यान्वित कर रहा है। इसके उप-घटकों में से एक वन धन विकास कार्यक्रम है, जिसे ट्राइफेड (भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड) के माध्यम से लागू किया जाता है। यह वन धन स्वयं सहायता समूहों (वीडीएसएचजी) के रूप में जानी जाने वाली ग्राम स्तर की प्राथमिक एसएचजी इकाइयों को अतिरिक्त आय उत्पन्न करने के लिए उद्यम मार्ग पर जोर देता है। प्रत्येक वीडीएसएचजी में 20 वनवासी शामिल होते हैं जो लघु वन उत्पादों के संग्रहण, प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन का कार्य करते हैं। ऐसे 15 वीडीएसएचजी को 300 सदस्यों तक के प्रत्येक वीडीवीके में शामिल किया जाता है ताकि क्षेत्र में वीडीवीके संगठन में एक अंतर्निहित क्षमता सृजित करने के लिए परिकल्पित प्रशिक्षण, कच्चे माल के एकत्रीकरण, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और विपणन कार्यों में बड़े पैमाने की किफायतों का लाभ उठाया जा सके। यह योजना वीडीवीके सदस्यों को वर्ष भर आजीविका सुनिश्चित करने के लिए कृषि, फूलों की खेती, औषधीय पौधों आदि जैसी अन्य कार्यकलापों को करने की भी अनुमति देती है।

अगस्त, 2019 से वन धन योजना के शुभारंभ के बाद से, ट्राइफेड ने देश में 9.00 लाख से अधिक लाभार्थियों से जुड़े 3000 से अधिक वन धन विकास केंद्र समूहों (50000 से अधिक वन धन स्वयं सहायता समूह) को मंजूरी दी है। यह परिकल्पना की जाती है कि यह हमारे देश के जनजातीय समुदाय की समग्र अर्थव्यवस्था में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

पश्चिम बंगाल जनजातीय विकास सहकारी निगम लिमिटेड, कोलकाता के माध्यम से 6719 लाभार्थियों को शामिल करते हुए 22 वीडिवीके की स्थापना के लिए पश्चिम बंगाल को 329.35 लाख रुपये की राशि जारी की गई है। इसमें झारग्राम जिले के 4 वीडिवीके शामिल हैं।

(ख) तथा (ग): जनजातीय कार्य मंत्रालय ने एमएफपी के लिए एमएसपी की योजना के तहत एमएफपी के प्रापण के लिए परिक्रामी निधियों के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य को 201.72 लाख रुपये की राशि जारी की है। राज्य कार्यान्वयन एजेंसी - पश्चिम बंगाल जनजातीय विकास सहकारी निगम लिमिटेड, कोलकाता ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार पश्चिम बंगाल राज्य में जनजातीय एमएफपी संग्रहकर्ताओं से 80.03 लाख रुपये के मूल्य के एमएफपी का प्रापण किया।

एमएफपी के नाम	वित्तीय वर्ष 2018-19		वित्तीय वर्ष 2019-20		कुल योग (दिसंबर 2021 तक)	
	प्रापण		प्रापण		प्रापण	
	मात्रा मेट्रिक टन में	मूल्य (रु. लाख में)	मात्रा मेट्रिक टन में	मूल्य (रु. लाख में)	मात्रा मेट्रिक टन में	मूल्य (रु. लाख में)
साल बीज	248.463	49.69	68.225	13.65	316.69	63.34
साल पत्ता			2.045	0.72	2.05	0.72
महुआ फूल			0.400	0.13	0.40	0.13
महुआ बीज			0.327	0.09	0.33	0.09
नीम बीज			0.197	0.05	0.20	0.05
करंज बीज			0.300	0.07	0.30	0.07
आंवला			1.000	0.15	1.00	0.15
बहेडा			0.100	0.02	0.10	0.02
गिलोय			33.460	13.38	33.46	13.38
जामुन बीज			0.615	0.25	0.62	0.25
चिरौंजी बीज			0.050	0.06	0.05	0.06
अपांग पौधा			0.03	0.008	0.03	0.01

(प्लांट)						
कालमेघ			0.004	0.001	0.00	0.001
कुसुम बीज			0.4	0.09	0.40	0.09
सतावरी			1.2	1.28	1.20	1.28
भिलावा (मार्किंग नट)			0.005	0.001	0.01	0.001
मधनासिनी			0.8	0.38	0.80	0.38
कुल	248.463	49.69	109.158	30.34	357.62	80.03

इसके अलावा, वर्ष 2018-19 के दौरान हाट बाजारों के आधुनिकीकरण और प्राथमिक एकत्रीकरण/भंडारण सुविधाओं की स्थापना के लिए पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को 455.44 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई है।

इसके अलावा, जैसा कि ट्राइफेड द्वारा सूचित किया गया है, जनजातीय उत्पादों के विकास और विपणन के लिए संस्थागत सहायता योजना के तहत, ट्राइफेड ने पश्चिम बंगाल के कारीगरों से जनजातीय उत्पादों की निम्नवत खरीद की:

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	राशि लाख रु. में.
1.	2017-18	31.10
2.	2018-19	86.95
3.	2019-20	240.93
4.	2020-21	81.88
5.	2021-2022 (27.02.2022 तक)	172.90
	कुल:	613.76
